Mining Policy during Fourth Plan

*855. **Shri Shiva Chandra Jha:** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the mining industry in respect of coal, gold and iron ore is under private ownership; and

(b) if so, Government's policy in this regard during the Fourth Five Year Plan?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) Mining Industry of Coal is mostly under private ownership. Gold mining industry is however entirely in the public sector. Regarding iron ore, the bulk of production is accounted for private sector mines

(b) The policy of Government about mining industry in respect of these minerals is laid down in the Industrial Policy Resolution of 30th April, 1956

No change in this policy is envisaged in the Fourth Five Year Plan.

छोटी कार का निर्माण

*856. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० सूर्यप्रकाश पुरी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री राजाराम शर्मा :
श्री मेघचन्द्र :
श्री वीरेश्वर द्विवेदी :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :

क्या औद्योगिक विकास तथा स्वदेश-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने छोटी कार के निर्माण के सम्बन्ध में अपनी अस्वीकृति व्यक्त की थी;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय प्रायः लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है; और

(घ) इस कारखाने के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी, और विभिन्न देशों से कितना कितना सहयोग प्राप्त होने की संभावना है और उनकी शर्तें तथा निबन्धन क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा स्वदेश-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित विकास तथा विनियोजन कार्यक्रम में उद्योग मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि प्रति वर्ष 50,000 सवारी कारों का निर्माण करने के लिए परियोजना जिन में हल्की मोटर गाडियां भी शामिल हैं, सरकारी क्षेत्र में शामिल की जाय जिसमें कुल विनियोजन 35 करोड़ रु० का होगा । लेकिन फिर भी इसे अभी मसौदे की रूपरेखा में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित परियोजना के बारे में इसे कार्यान्वित किये जाने पर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जावेगा या गैर सरकारी क्षेत्र में अन्तिम निर्णय अभी नहीं किया गया है । फिर भी सरकार इतने बड़े विनियोजन को ध्यान में रखते हुए यह अधिक पसंद करेगी कि यदि इस परियोजना के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होगी कि ये उपलब्ध हों सकें तो इसे सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाय ।

(घ) अनुमान लगाया है कि 50,000 कारों की वार्षिक क्षमता वाले कारखाने की स्थापना करने पर विनियोजन 35 करोड़

रुपये से लेकर 40 करोड़ रुपये तक होगा जिसमें विदेशी पूंजी का लगभग 15 करोड़ रुपये होगा। गैर सरकारी या सरकारी क्षेत्र में जिन भारतीय और विदेशी पार्टियों ने कम कीमत की कार बनाने का प्रस्ताव किया है उनसे प्रारम्भिक बातचीत की गई है। प्रत्येक पार्टी से जितने भी प्रस्ताव किये थे यह कहा गया है कि वह प्रस्ताव का समुचित ब्यौरा प्रस्तुत करे जिससे सरकार उसकी आर्थिक सम्भाव्यता को जांच कर सके। ये ब्यौरे प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस मामले में अन्तिम निर्णय किये जाने से पहले सभी योजना की यथोचित जांच की जायेगी।

Corporation for Sick Textile Mills

*858. **Shri G. S. Mishra:** Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 243 on the 2nd June, 1967 and state:

(a) the initial capital investment and running charges of the Corporation proposed to be set up to run the sick textile mills;

(b) how many sick textile mills, it proposes to run in the first instance;

(c) the factors which have been taken into consideration in deciding over the choice of the closed textile mills;

(d) whether the foreign exchange part of this scheme is provided under Aid Loan or free resources, and

(e) whether Government are thinking of establishing any such type of concern in the public sector for raising the cotton production?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) The matter is under consideration.

(b) to (d). Do not arise at this stage.

(e) No, Sir.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की उत्पादन क्षमता

*859. **श्री महाराज सिंह भारती:** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 26 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 692 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के भारी मशीन निर्माण संयंत्र के 15,000 मीट्रिक टन के वर्तमान उत्पादन को उसका उत्पादन लक्ष्य मान लिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान उत्पादन के लक्ष्य से कम रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस देश में मशीनों की मांग को पूरा करने के लिए यह क्षमता पर्याप्त है और यदि नहीं, तो उपरोक्त फैक्टरी के विस्तार पर रोक लगाने के क्या कारण हैं, जबकि विदेशों से मशीनों का आयात करना पड़ता है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। भारी मशीन निर्माण संयंत्र 15,000 मीट्रिक टन के मशीनी उपकरण बनाने के साथ साथ 1967-68 में 11,240 मीट्रिक टन के औद्योगिकीय ढांचे भी बनायेगा जिसे कुल आयोजित उत्पादन 26,240 मीट्रिक टन हो सके। उत्पादन प्रतिवर्ष लगातार बढ़ता जायेगा और अन्त में बढ़कर 80,000 मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगा। क्षमता का उपयोग किसी वर्ष विशेष में प्राप्त आर्डरों पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, हां। विस्तार पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि उसे मांग के द्वारा उचित ठहराया जा सकता हो।